303.00 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की मांग की गई है।

(ग) विद्यमान योजना के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए राहत और पुनर्वास उपाय शुरू करने के लिए प्रत्येक राज्य के वास्ते एक आपदा राहत कोष बनाया गया है। गुजरात का वार्षिक आपदा राहत कोष 85 00 करोड़ रुपए है जिसमें केन्द्र का अंशदान 63.75 करोड़ रुपए तथा राज्य का अंशदान 21.25 करोड़ रुपए है। गुजरात सरकार को वर्ष 1994-95 के लिए आपदा राहत कोष सम्पूर्ण केन्द्रीय हिस्सा निर्मुक्त कर दिया गया है।

सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण कार्य

653. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार की ओर से सरदार सरोवर परियोजना पर चल रहे निर्माण कार्य की कोई समीक्षा की गई है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस निर्माण कार्य की प्रगति का ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस परियोजना को कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (पी० के० थुंगन) : (क) नर्मदा जल विवाद अधिकरण पंचाट के प्रावधानों के तहत गठित नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण तथा सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण कार्य की प्रगति की आवधिक समीक्षा कर रहे हैं।

(ख) और (ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण में प्रगति

क. 30-6-1994 तक की स्थिति के अनुसार भौतिक प्रगति

I. बांध तथा बिजली घर :

क्र. सं.	घटक	खुदाई %	कंक्रीटिंग %	ड्रिलिंग %
1	मुख्य बांध	85.59	67 27	75.28
2	नदी तल विद्युत बिजली घर	91.24 (खुली) 83.62 (भूमिगत)		
3	नहरशीर्ष बिजली घर	पूर्णता पर	93.00	
4	वैडगम सैडल बांध	पूर्ण	पूर्ण होने वाला है	

II नहरें तथा वितरण प्रणाली

नर्मदा मुख्य नहर की 0-144 कि.मी. तक की पहुंच का निर्माण कार्य कुल लंबाई को खण्डों में विभाजित कर प्रगति पर है। नर्मदा मुख्य नहर की 236.58 से 263.165

क.मी. तक की लंबाई में मिट्टी का कार्य भी शुरू किया गया है। नर्मदा मुख्य नहर तथा शाखा नहरों की इन पहुंचों के कार्य की प्रगति 30-6-94 की स्थिति के अनुसार इस प्रकार है।

	नर्मदा मुख्य नहर	शाखा नहर
1. मिट्टी कार्य	91.60%	68.30%
2. पक्का करना	73.46%	38.83%
3. संरचनात्मक कंक्रीट	50%	36.87%

(ख) 30-9-1994 की स्थिति के अनसार वित्तीय प्रगति :

सितम्बर, 1994 तक 3486.24 करोड़ रुपए का व्यय किया गया।

सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण कार्यक्रम :

	पूर्ण किए जाने का वर्ष
1. बांध	1998
2. नहर एवं कमांड क्षेत्र विकास कार्य	2000 (संशोधित)
3. जल विद्युत	1999 (संशोधित)

Fertile land turning saling in Karnataka

654. SHRI B. K. HARIPRASAD: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether thousands of acres of highly fertile land in the Thungabhadra project area of Karnataka, are turning saline due to lack of drainage as mentioned in Economic Times dated 20th November, 1994;

(b) whether Government are in possession of a report of a study conducted by the Area Development Board under the auspices of Institute for Social and Economic Chance, Bangalore, of its survey of Gulbarga, Bidar, Bellary and Rajchur districts of Karnataka; and

(c) what are the measures recommended in the report to reclaim the land and increase crop yields and whether Government are seriously considering these measures for early implementation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) As per the survey conducted during 1991-92, an area of 43,415 Hectares has been affected by salinity/alkalinity and water-logging. Main causes of the problem include lack of proper drainage and improper management of water in the upper reaches.

(b and (c) No, Sir. However, the Government of Karnataka have taken up preventive measures or effective utilisation of irrigation water through Command Area Development activities. Land reclamation measures have also been undertaken by Command Area Development Authority since 1979-80 and an area of 2,300 hectares has been reclaimed so far.